अगस्त, 2024 , वर्ष : 45 अंक : 08

www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

न्यूयॉर्क में करीब २७,००० अनुयायियों ने परम पावन दलाई लामा के लिए दीर्घायु प्रार्थना की

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

अगस्त, 2024 , वर्ष : 45 अंक : 08

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारतीय स्वतंत्रता का ७८वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया

प्रधान संपादक
ताशी देकि

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
मिग्मार छमचो

वितरण प्रबंधक
नावांग छोडेंन

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

- न्यूयॉर्क में करीब १७,००० अनुयायियों ने परम पावन दलाई लामा के लिए दीर्घायु प्रार्थना की 1
- परम पावन दलाई लामा धर्मशाला लौटे 2
- केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारतीय स्वतंत्रता का ७८वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया 3
- निर्वासित तिब्बती संसद की ओर से दिल्ली में तिब्बत के पक्ष में अभियान 4
- श्री भर्तृहरि महताब और श्री तापिर गाओ ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंटरी फोरम फॉर तिब्बत के क्रमश: नए संयोजक और सह-संयोजक बने 5
- तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं के फोरम में भाग लिया 6
- तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिनिधि सभा के डिप्टी स्पीकर और ऑस्ट्रेलियन ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के सदस्यों से मुलाकात की 7
- भारत-तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तिब्बत के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया तथा वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया गया 8
- कालोन डोल्मा ग्यारी ने धर्मशाला में तिब्बत के पुराने समर्थक श्री डॉ. इंद्रेश कुमार का स्वागत किया 9

समाचार -

- चीन : तिब्बतियों के जबरन गायब करने को रोकें, जबरन गायब किए गए सभी लोगों के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के मानकों के अनुरूप पुष्टि करें 10
- . तिब्बती मुद्दों की विशेष समन्वयक ने परम पावन के समक्ष अमेरिका द्वारा तिब्बती मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की 11
- तिब्बत नीति संस्थान ने पूर्व भारतीय राजदूत दिलीप सिन्हा के साथ उनके हालिया कार्य 'तिब्बत में इंपीरियल गेम्स' पर एक टॉक सत्र आयोजित किया। 12
- चीन को तिब्बती मानवाधिकार कार्यकर्ता शेरिंग सो के उत्पीड़न को रोकना चाहिए 13

11

12

मुद्रक एवं प्रकाशक
जमयांग दोरजी द्वारा
नोरबू ग्राफ़िक्स , 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार , लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट

coordinator@indiatibet.net

अपनी बात ◆ तिब्बत का चीनी नाम रखकर तिब्बत की पहचान मिटाने की खतरनाक साजिश

तिब्बती धर्मगुरु परमपावन दलाईलामा लगभग दो माह बाद अमरीका से स्वस्थ-सकुषल हिमाचल प्रदेष के कांगड़ा जिलांतर्गत धर्मषाला गत 28 अगस्त, 2024 को लौट आये हैं। अपने घुटनों की सर्जरी के लिये वे अमरीका गये थे। चिकित्सकों को विष्वास है कि छः माह बाद वे पूर्व की भाँति चलने लगेंगे। दलाईलामा की सकुषल वापसी से उनके अनुयायी एवं समर्थक काफी प्रसन्न हैं। तिब्बती समुदाय तथा तिब्बत समर्थकों के साथ अन्य लोग भी दलाई लामा के दीर्घजीवन की कामना करते हैं।

इसी अगस्त माह में तिब्बती समुदाय ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार एवं भारतीय समाज को उत्साहपूर्वक बधाई दी। निर्वासित तिब्बत सरकार ने इस अवसर पर समर्थन एवं सहयोग देते रहने के लिये भारत के प्रति कृतज्ञतापूर्ण आभार प्रकट किया। ध्यातव्य है कि हिमाचल प्रदेष की धर्मषाला से संचालित निर्वासित तिब्बत सरकार वास्तव में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित सरकार है। इसने 15 अगस्त, 2024 को फिर से स्मरण कराया कि संकटग्रस्त तिब्बतियों को सन् 1959 में भारत ने शरण दी थी। इसके पष्चात् लगातार जारी चीनी विरोध के बावजूद भारत तिब्बती कला-संस्कृति-इतिहास-पहचान तथा ज्ञान-विज्ञान के संरक्षण-संवर्धन के लिये भरपूर सहयोग कर रहा है। इससे प्रमाणित होता है कि तिब्बत के तत्कालीन राजप्रमुख एवं धर्मप्रमुख दलाईलामा ने गुरुभूमि भारत में शरण लेकर अच्छा किया था।

अच्छी बात है कि भारतीय समाज भी तिब्बती समुदाय के प्रति हार्दिक आभार प्रकट कर रहा है। दलाईलामा देष-विदेष में प्राचीन नालंदा परंपरा का गुणगान कर रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति एवं गौरव को बढ़ाने में लगे हैं। भारत में विभिन्न रिलिजन (मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय) के अनुयायी हैं। उनके बीच सामंजस्य, सहयोग तथा सद्भाव बढ़ाने के लिये वे सदैव तत्पर हैं। उनके अनुसार पंथनिरपेक्षता (सेकुलरिज्म) का अर्थ है सर्वपंथसमादरभाव। प्रत्येक पंथ के अनुयायी अन्य सभी पंथों के प्रति समान आदर का भाव रखें।

चीन सरकार ने तिब्बत में व्यापक पैमाने पर स्थानों, संस्थानों, स्थलों तथा महत्वपूर्ण प्रतीकों के नाम बदल दिये हैं। भारत में भी विदेषी आक्रमणकारियों ने ऐसा किया था। इस कदम से पराधीन देष के लोगों को पूर्णतः मानसिक रूप से गुलाम बना दिया जाता है ताकि आजादी मिलने पर भी वे बदले हुए नामों से ही जुड़े रहें। आजादी के बाद भी पुराने नामों को अपनाते हुए उन्हें शर्म आती है। वे इस प्रक्रिया में अपने वास्तविक पूर्वजों को छोड़कर नये-नये पूर्वज भी अपना लेते हैं।

तिब्बती पहचान मिटाने में लगी चीन सरकार के नये प्रयास का व्यापक विरोध होना चाहिये। उसने तिब्बत को "षिजांग" कहना-लिखना प्रारम्भ कर दिया है। विदेषी आक्रमणकारियों ने भारत को भी "इंडिया" कहना-लिखना प्रारम्भ कर दिया था। दुर्भाग्यवष आज भी भारत का यह नया नाम प्रचलन में है। तिब्बत को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचाने के लिये आवष्यक है कि चीन द्वारा दिये नये नाम का विरोध किया जाये। तिब्बत को तिब्बत ही कहा जाये। ज्ञातव्य है कि चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान को "षिंजियांग"नाम दे रखा है। किसी देष की पहचान को मिटाने का प्रभावी उपाय है उस देष का नया नाम रख देना। अपने गाँव या पड़ोस में भी आपको ऐसे व्यक्ति मिल जायेंगे जिनके असली के साथ नकली नाम भी हैं। ऐसे लोगों को डाकघर वाले भी नहीं पहचान पाते। चीन सरकार सभी जगह तिब्बत के नये चीनी नाम का प्रयोग कर रही है। चीन के इस षड्यंत्रपूर्ण दुष्प्रचार से तिब्बत को बचाना हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है।

तिब्बत विरोधी चीन समर्थक तिब्बत के चीनी नाम का प्रयोग करने लगे हैं। भारत में ऐसी लॉबी काफी सक्रिय है। यह भारत विरोधी चीनी षड्यंत्र में संलग्न है। यह भारत एवं तिब्बत के विरोध में चीन सरकार के साथ है। इसी लॉबी के बल पर चीन ने अरुणाचल प्रदेष में कई स्थानों के नाम बदल दिये थे। चीन सरकार अरुणाचल प्रदेष को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताती है। भारत सरकार ने बदले में तिब्बत के कई स्थानों के पारंपरिक नाम फिर से रखने का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि चीन सरकार इन्हें हटाकर नये चीनी नाम दे चुकी है। चीन सरकार तिब्बत को नया नाम देकर पूरे तिब्बती संघर्ष को भ्रमित करने में लगी है। विदेषी आक्रमणकारियों ने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को भी इसी तरह भ्रमित किया था।

तिब्बत के आम्दो प्रांत में चीन सरकार ने एक महत्वपूर्ण तिब्बती स्कूल को बंद कर दिया है। इससे तिब्बती भाषा, संस्कृति तथा गौरवपूर्ण धरोहर को नष्ट करने में मदद मिलेगी। भारत में भी विदेषी आक्रमणकारियों ने भारतीय षिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक-ऐतिहासिक केन्द्रों, गौरवपूर्ण प्रतीकों तथा स्मारकों के साथ यही किया था। कुख्यात बख्तियार खिलजी ने प्राचीन भारत के विष्व प्रसिद्ध नालंदा विष्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवा दी थी। यही कार्य ब्रिटिष शासन में मेकालेवादी षिक्षा ने किया। यही कार्य चीन सरकार सन् 1959 से तिब्बत में कर रही है। इस पर यथाषीघ्र रोक हेतु चीन सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ाना होगा।

जानबूझकर चीन सरकार तिब्बत की निर्वासित सरकार एवं दलाईलामा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बंद पड़ी वार्ता पुनः प्रारम्भ नहीं कर रही है। तिब्बत में व्यापक पैमाने पर वह मानवाधिकारों का हनन तथा नरसंहार कर रही है। समस्या का समाधान सार्थक वार्ता से संभव है। विष्वजनमत इसी पक्ष में है। बंद पड़ी वार्ता यथाषीघ्र पुनः प्रारम्भ होनी चाहिये।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

◆ १. न्यूयॉर्क में करीब १७,००० अनुयायियों ने परम पावन दलाई लामा के लिए दीर्घायु प्रार्थना की

२३ अगस्त, २०२४

न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर के बाहरी इलाके एलमोंट में २२ अगस्त २०२४ की सुबह उत्तरी अमेरिका में रह रहे तिब्बती, मंगोलियाई और हिमालयी समुदायों के लगभग १७,००० अनुयायियों ने एकत्र होकर सामूहिक रूप से परम पावन दलाई लामा की दीर्घायु के लिए तेनशुग प्रार्थना की।

परम पावन २० अगस्त २०२४ को सिरैक्यूज़ से न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे थे।

परम पावन जब २० अगस्त की सुबह यूबीएस एरिना पहुंचे तो उनका स्वागत पारंपरिक चेमार और चांगफू अर्पण कर और धुंग और ग्यालिंग बजाकर किया गया। मंच पर परम पावन के आसन ग्रहण करते ही वहां उपस्थित २०० से अधिक भिक्षुओं, भिक्षुणियों और साधकों सहित सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हुए। इसके बाद परम पावन दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के उत्तरी अमेरिका स्थित कार्यालय में प्रतिनिधि डॉ. नामग्याल चोएड्रुप ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने परम पावन द्वारा शल्य चिकित्सा के बाद फिजिकल थेरेपी और सेहत में सुधार की प्रक्रिया चलते रहने के बीच ही संक्षिप्त प्रवचन देने के लिए समय निकालने का अनुरोध स्वीकार करने के लिए सभी लोगों की ओर से उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया।

उन्होंने कहा कि आज की हार्दिक तेनशुग प्रार्थना सभी भव्य प्राणियों के हित में परम पावन के दीर्घायु होने के लिए है।

डॉ. चोएड्रुप ने परम पावन के उपचार के लिए यहां तक की यात्रा में सहायता प्रदान करने के लिए हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी की मेडिकल टीम, अमेरिका सरकार, विशेष रूप से तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक के कार्यालय और विदेश विभाग की राजनयिक सुरक्षा सेवा, शुभचिंतकों और संगठनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने १९ अगस्त के कार्यक्रम की मेजबानी बहुत ही कम समय में करने में मदद करनेवाले लोगों और संगठनों को भी धन्यवाद दिया। दुनिया भर के सभी भक्तों और शुभचिंतकों की ओर से परम पावन के निरंतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए प्रतिनिधि ने यह भी प्रार्थना की कि वह दिन दूर न हो जब परम पावन तिब्बत लौट सकें और तिब्बत में और निर्वासन में रहने तिब्बती एक बार फिर एक साथ हों सकें। डॉ. चोएड्रुप की टिप्पणियों के बाद परम पावन दलाई लामा के ९०वें जन्मदिन के लिए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के पांच स्कूलों के ४०० तिब्बती छात्रों (७ से १४ वर्ष की आयु) द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया गया।

परम पावन ने अपने संबोधन में उन समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं के बारे

में व्याख्यान दिया, जिन्हें तिब्बतियों के तीनों चोलखाओं के नेतृत्व में पूरा हिमालयी समुदाय संरक्षित करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'फिर, तिब्बत के लोग ग्यालवा तेनजिन ग्यात्सो में पर विश्वास करते हैं, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो भी संभव है, कर रहा हूं।'

'हर कोई काम कर रहा है। यहां तक कि मैं भी १०० से अधिक वर्षों तक जीवित रहूंगा।'

'तिब्बत के लोगों में अकल्पनीय दृढ़ संकल्प और साहस है। भले ही वे चुनौतियों का सामना कर रहे हों, लेकिन वे अपनी तिब्बती पहचान को भी कायम रखे हुए हैं।'

'इस दुनिया में जो लोग बौद्ध नहीं भी हैं, वे भी हमारी आध्यात्मिक विरासत की प्रशंसा करते हैं। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऐसा करते रहना चाहिए।'

'इसलिए कृपया उत्साह बनाए रखें और यह मानकर चलें कि इसमें हमारी संस्कृति का योगदान है। धोमी से ल्हामो थोंडुप आपका नेतृत्व कर रहे हैं। लद्दाख से खाम तक के क्षेत्र के सभी लोग दलाई लामा के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यह श्रद्धा और प्रेम तिब्बती संस्कृति के लिए है, यह न केवल सामाजिक क्षेत्र तक सीमित है बल्कि हमारी आध्यात्मिक विरासत के लिए भी है। बौद्ध धर्म की तिब्बती परंपरा सबसे विस्तृत है। तिब्बत और तिब्बतियों के लिए हाल की चुनौतियां एक प्रकार का आशीर्वाद है क्योंकि इसने हमें अपनी संस्कृति के मूल्य को जानने-समझने में सक्षम बनाया है। मैं सभी मित्रों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।'

'मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मैं इसी तरह के स्थान पर था। मैं लोगों के बीच बैठा था और वहाँ बुद्ध मुझे अपनी ओर आने के लिए इशारा कर रहे थे। मैं उनके पास गया। उस समय मेरे पास उन्हें देने के लिए केवल कुछ चॉकलेट थीं, जो उन्होंने बहुत पसंद आईं। मैंने यथासंभव बुद्ध धर्म की सेवा की है और ऐसा करना जारी रखूंगा।'

'आज, दुनिया भर में बौद्ध धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है। यहां तक कि चीन में भी तिब्बती बौद्ध धर्म में रुचि बढ़ी है।'

तत्पश्चात, बोधिचित्त प्रतिज्ञा प्रदान करते हुए परम पावन ने कहा कि यह कितना अद्भुत सिद्धांत है कि बोधिचित्त स्वयं के हित के साथ-साथ दूसरों के हित के लिए भी आवश्यक है।

तत्पश्चात परम पावन ने बुद्ध मंत्र, तारा मंत्र, चेनरेसिग मंत्र, जम्पेलयांग मंत्र, हेयाग्रीव मंत्र, मेनला मंत्र और गुरु रिनपोछे मंत्र का मौखिक जाप किया।

जैसे ही तेनशुग प्रार्थना शुरू हुई, अमेरिका और कनाडा के ३० तिब्बती संघों के साथ-साथ कलमीकियाई, बुरातियाई, मंगोलियाई समुदायों के साथ-साथ शेरपा, तमांग, ह्योल्मो, भूटानी, लिमी, मुस्तांग, मनांगी, नुबरी और अन्य हिमालयी समुदायों और न्यूयॉर्क स्थित तिब्बती गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि प्रतीकात्मक रूप से खटग लहराते हुए मंच के सामने से जुलूस के रूप में गुजरे।

अंत में, आय-व्यय का लेखा-जोखा के अलावा प्राप्त दान के शेष के उपयोग के बारे में पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया। समारोह में उपस्थित अनुयायियों में चीनी, कोरियाई, ताइवानी, अमेरिकी समुदायों के लोग भी शामिल हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सेवारत और पूर्व अधिकारी, जिनमें पूर्व सर्वोच्च न्याय आयुक्त, कालोन त्रिसूर, सिसूर, कासूर, पूर्व सांसद, पूर्व सचिव के साथ ही सांसदों ने भी समारोह में भाग लिया।

हालांकि कार्यक्रम को अल्प सूचना पर आयोजित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में भक्तों ने इसमें शिरकत की। पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्दिष्ट समय पर ऑनलाइन टिकट कार्यालय की घोषणा और उसके समय पर खुलने के लिए पूर्व व्यवस्था की गई थी। सारे टिकट दो घंटे के भीतर बिक गए। मेहमानों के लिए अलग रखे गए कुछ टिकट भी बाद में जनता के लिए जारी किए गए। वाशिंगटन, डीसी, टोरंटो आदि के तिब्बती समुदायों ने बसें किराए पर ले रखी थीं, ताकि उनके क्षेत्र के भक्त न्यूयॉर्क में परम पावन से आशीर्वाद प्राप्त करने के इस विशेष अवसर का लाभ उठा सकें।

समारोह का समापन शुभ नामथर (ओपेरा) के गायन के साथ हुआ, जिसके बाद परम पावन एरिना से अपने होटल के लिए प्रस्थान कर गए।

तिब्बत कार्यालय के अनुरोध पर अमेरिका के चोलुल मोनलम एसोसिएशन द्वारा समारोह के लिए प्रारंभिक प्रार्थना (शेदुप) १८ से २१ अगस्त २०२४ तक तिब्बती सामुदायिक केंद्र में आयोजित की गई थी।

◆ ०२. परम पावन दलाई लामा धर्मशाला लौटे

darailama.com २८ अगस्त, २०२४

थेकचेन चोलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। आज २८ अगस्त की सुबह परम पावन दलाई लामा न्यूयॉर्क से अपनी यात्रा पूरी करके धर्मशाला लौट आए। न्यूयॉर्क में वे पिछले दो महीनों से अपने घुटनों का इलाज करवा रहे थे। ज्यूरिख में २७ अगस्त को एक दिन विश्राम के लिए वे रुके थे। उसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हुए।

धर्मशाला की उड़ान के लिए आज का मौसम अनुकूल था। इसलिए उड़ान समय पर रवाना हुई और लगभग आधे घंटे पहले ही धर्मशाला में उतर गई। परंपरा के अनुसार, गग्गल हवाई अड्डे पर परम पावन का स्वागत सिक्योंग पेन्पा शेरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर भिक्षु खेंपो सोनम तेनफेल ने किया। उनका स्वागत करने के लिए हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और बौद्ध धर्म जैसे विभिन्न धार्मिक परंपराओं के स्थानीय प्रतिनिधि और कई शुभचिंतक वहां मौजूद थे। परम पावन ने उन सबका गर्मजोशी से स्वागत किया।

परम पावन का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में तिब्बती सिविल लाइंस में मेन-शी-खांग के बाहर हरि कोटि चौक पर गंगचेन कइशोंग के द्वार पर और मुख्य तिब्बती मंदिर शुगलागखांग के नीचे और बगल की सड़क पर जमा थे। भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने अपने पीले धर्म वस्त्र पहन रखे थे, जबकि आम लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनमें से कई लोगों के हाथों में सफेद रेशमी स्कार्फ और चमकती धूपबत्ती थी और उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। परम पावन ने गुजरते समय उन्हें देखकर हाथ हिलाया और खुशी से मुस्कुराए।

ताशी शोल्पा नर्तकियों के तीन समूहों ने हवाई अड्डे पर, गंगचेन कइशोंग के द्वार पर और शुगलागखांग के पास उत्साह से नृत्य और गायन प्रस्तुत किया।

परम पावन के निवास के द्वार के चारों ओर एकत्र हुए पूर्व कालोन, सचिव और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी कार के गुजरने पर उन्हें नमस्कार किया। उनमें से एक ने टिप्पणी की कि आम तौर पर ऐसा लग रहा था कि आज सुबह धर्मशाला में फिर से जान आ गई है।

◆ ०३. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारतीय स्वतंत्रता का ७८वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया

१५ अगस्त, २०२४

धर्मशाला। भारतीय स्वतंत्रता की ७८वीं वर्षगांठ पर इस खुशी के दिन को मनाने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारतीय भाई-बहनों के साथ गंगचेन कइशोंग में एक संक्षिप्त समारोह का आयोजन किया।

इस समारोह में निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेंपो सोनम तेनफेल, सिक्योंग पेन्पा शेरिंग, शिक्षा मंत्री थरलाम डोल्मा चांगरा, सुरक्षा मंत्री डोल्मा ग्यारी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सचिव शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत सिक्योंग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने और भारत का राष्ट्रगान गाने के साथ हुई। इसके बाद सिक्योंग ने मीडिया से बात की और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार और यहां के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, 'तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों की ओर से हम ७८वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भारत के नेतृत्व और लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं।'

तिब्बत के नेतृवर्ग ने पिछले साठ वर्षों से अधिक समय से इतिहास के सबसे बुरे दौर में तिब्बती शरणार्थियों को भारत द्वारा ईमानदारी से दी गई सहायता को स्वीकार किया है। इस सहायता के लिए तिब्बती नेतृवर्ग ने प्रत्येक तिब्बती की ओर से भारत सरकार और यहां के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

सिक्योंग ने आगे कहा, 'यह विडंबना है कि भारत को १९४७ में स्वतंत्रता मिली और इसके तीन साल बाद हमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। वास्तव में, दुनिया भर के कई देशों ने विशेष रूप से द्वितीय विश्व

युद्ध के बाद, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। लेकिन दुर्भाग्य से, कम्युनिज्म की लहर ने तिब्बत के क्षेत्र को चीन के जबरदस्त कब्जे में ले लिया। हम अभी भी यहां राजनीतिक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और हम भारत की स्वतंत्रता से प्रेरणा भी लेते हैं कि हम भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तिब्बत वापस लौटेंगे। हम एक ऐसे समुदाय के रूप में अपने देश लौटेंगे जो भाषा, संस्कृति, धर्म, जीवन शैली और विशेष रूप से पर्यावरण के संदर्भ में अपनी पहचान के संरक्षण और संवर्धन करते हुए स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। यह न केवल तिब्बत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आप भारतीयों के लिए जश्न मनाने का खुशनुमा अवसर है, लेकिन हम तिब्बती भी आपके साथ इसका आनंद लेते हैं। साथ ही, हम उस दिन के बारे में भी सोचते हैं और उसका इंतजार करते हैं जब हमें भी अपनी आज़ादी का जश्न मनाने का मौका मिलेगा।

◆ ०४. निर्वासित तिब्बती संसद की ओर से दिल्ली में तिब्बत के पक्ष में अभियान

tibet.net, ०६ अगस्त, २०२४ | दिल्ली, ०५ अगस्त २०२४

निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेंपो सोनम तेनफेल के नेतृत्व में निर्वासित तिब्बती संसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत के पक्ष में भारतीय सांसदों का मत तैयार करने के प्रयासों की शुरुआत की। उनका यह कार्यक्रम ०९ अगस्त, २०२४ तक जारी रहेगा।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दो समूहों में विभाजित होकर चीनी कम्युनिस्ट शासन में तिब्बती लोगों की गंभीर स्थिति पर भारतीय नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए आगामी दिनों में अपनी पक्षधरता प्रयासों को जारी रखेंगे। पहले समूह का नेतृत्व स्पीकर खेंपो सोनम तेनफेल करेंगे। इस समूह में सांसद गेशे ल्हारम्पा अटुक शेटेन और सांसद शानेत्संग धोंडुप ताशी शामिल हैं जबकि दूसरे समूह में सांसद लोपोन थुपतेन ग्यालत्सेन, सांसद गेशे न्गाबा गंगरी, सांसद गेशे अटोंग रिनचेन ग्यालत्सेन और सांसद शेरिंग यांगचेन शामिल हैं।

पक्षधरता अभियान के दौरान, प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय की कार्यवाहक समन्वयक ताशी देकि, तिब्बती संसदीय सचिवालय के कर्मचारी तेनजिन पलजोर और तेनजिन शेरब, और निर्वासित तिब्बती संसद के दिल्ली स्थित समन्वयक फुंटसोक ग्यात्सो भी रहेंगे।

०५ अगस्त को तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने चार राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सात सांसदों से मुलाकात की। पहले समूह ने मध्य प्रदेश से भाजपा के लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, झारखंड से भाजपा के राज्यसभा सदस्य श्री दीपक प्रकाश, दिल्ली से भाजपा की लोकसभा सदस्य सुश्री बांसुरी स्वराज तथा कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर.के. खिरमे से मुलाकात की।

दूसरे समूह ने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, केरल के लोकसभा सदस्य श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, असम गण परिषद, असम के राज्यसभा सदस्य श्री बीरेंद्र प्रसाद बैश्य और असम गण परिषद के लोकसभा सदस्य श्री फणि भूषण चौधरी से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली विधानसभा का भी दौरा किया। वहां दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल (आप) और दिल्ली के 'आप' विधायक श्री मदन लाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी मेजबानी की।

अपनी बैठकों के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों पर आधारित भारत और तिब्बत के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला, जबकि चीन की बढ़ती विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों और चीनी सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया।

चूंकि फ्रीडम हाउस द्वारा तिब्बत को लगातार चौथे साल २०२४ के फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे कम स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया है, इसलिए प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बती भाषा और संस्कृति को खत्म करने के लिए बनाई गई चीन की नीतियों पर प्रकाश डाला। इसमें तिब्बती पहचान को प्रमुख हान संस्कृति में आत्मसात करने के उसके बढ़ते प्रयासों का विवरण दिया गया। इसमें छह साल की उम्र के बच्चों को आवासीय स्कूलों में जबरन भर्ती करना, सामूहिक डीएनए संग्रह अनिवार्य करना और गोलोक में गंगजोंग शेरिग नोरबू लोबलिंग (जिग्मे ग्यालत्सेन नेशनलिटीज वोकेशनल स्कूल) जैसे तिब्बती संस्थानों के साथ-साथ न्गाबा कीर्ति और ल्हामो कीर्ति मठों को हाल ही में बंद करना शामिल है।

इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने पीआरसी की कठोर नीतियों का विरोध करने वाले और परम पावन दलाई लामा की वापसी और तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग करते हुए २००९ से अब तक १५८ तिब्बतियों द्वारा किए गए आत्मदाह की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से गंभीर दमन के बावजूद अहिंसक प्रतिरोध के लिए तिब्बती लोगों की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अविभाज्य अधिकार को दोहराया।

उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की मध्यम मार्ग नीति पर प्रकाश डाला, जो चीन-तिब्बत संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने और तिब्बतियों और चीनी लोगों के बीच स्थिरता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने का पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीका है, जिसके बाद २००२ से २०१० तक तिब्बती और चीनी प्रतिनिधियों के बीच नौ दौर की वार्ता हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने निम्नलिखित बारह सूत्रीय अपील कीं।

- तिब्बत को चीन द्वारा अधिकृत कर लिए गए राष्ट्र के रूप में मान्यता दें।

- ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित तिब्बत के स्वतंत्र और संप्रभु अतीत को स्वीकार करें।

- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि करें।

- तिब्बती मूल के लोगों को 'अल्पसंख्यक' कहने जैसे चीनी लेबल से बचें और चीन के इस झूठे आख्यान को अस्वीकार करें। तिब्बत पर चीनी कब्जे को चीन का आंतरिक मुद्दा कहने से परहेज करें और तिब्बत को चीन का हिस्सा घोषित न करें। इस तरह के रुख चीन के उपनिवेशीकरण और तिब्बतियों की अधीनता का समर्थन होता है, जिससे तिब्बतियों की वास्तविक स्वतंत्रता के लिए बातचीत करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- चीन के जनवादी गणराज्य से आग्रह करें कि वह परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों या तिब्बती समुदाय के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेताओं के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के ठोस बातचीत में शामिल हो, जिसका उद्देश्य मध्यम मार्ग नीति के माध्यम से तिब्बत-चीन संघर्ष को हल करना और चीन के संविधान में प्रदत्त वास्तविक स्वायत्तता को प्राप्त करना है।

- जलवायु परिवर्तन अनुसंधान: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) से आग्रह करें कि वे तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों का चीन द्वारा दोहन और वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रतिकूल प्रभावों पर वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ करे।

- मानवाधिकारों की निगरानी: चीन पर दबाव डालें कि वह स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों को तिब्बत में मानवाधिकार स्थिति की निगरानी और रिपोर्ट करने की अनुमति दे। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों, विशेष रूप से राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन और मानवाधिकार रक्षकों पर ध्यान केंद्रित करने वालों को यथाशीघ्र तिब्बत की यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थायी निमंत्रण दें।

- तिब्बती राजनीतिक कैदियों की रिहाई: चीन सरकार से आग्रह करें कि वह सभी तिब्बती राजनीतिक कैदियों को बिना शर्त रिहा करे। इनमें ११वें पंचेन लामा गेधुन चोएक्यी न्यिमा भी शामिल हैं, जिनका ठिकाना और कुशलक्षेम १७ मई, १९९५ से अज्ञात है।

- दमनकारी नीतियों को रोकें: चीन से तिब्बती संस्कृति, भाषा और धर्म को खत्म करने के उद्देश्य से अपनी दमनकारी नीतियों को बंद करने का आह्वान करें।

- मानवाधिकार और तिब्बत-चीन संघर्ष: तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति को अनसुलझे तिब्बत-चीन संघर्ष के व्यापक संदर्भ में परिभाषित करें। विश्व नेताओं को तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और धार्मिक दमन पर चिंता व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें और इन दुर्व्यवहारों के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों को प्रतिबंधित करने के लिए मैग्निट्स्की अधिनियम को अपनाने की वकालत करें।

- अधिनायकवाद और दुष्प्रचार के खिलाफ विधायी ढांचा: चीन के नेटवर्क अधिनायकवाद और दुष्प्रचार अभियानों का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय विधायी ढांचा स्थापित करें, जो लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को खत्म करते हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाते हैं और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरे में डालते हैं।

- राजनयिक जुड़ाव को मजबूत करें: केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के साथ आधिकारिक और राजनयिक संबंधों का विस्तार करें, जो स्वतंत्र तिब्बत की पूर्व सरकार की विरासत को कायम रखता है और तिब्बती लोगों के वैध प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

- तिब्बती संसदीय सचिवालय की रिपोर्ट

◆ ०५. श्री भर्तृहरि महताब और श्री तापिर गाओ ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंटरी फोरम फॉर तिब्बत के क्रमश: नए संयोजक और सह-संयोजक बने

tibet.net, ०८ अगस्त, २०२४

धर्मशाला। ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंटरी फोरम फॉर तिब्बत (एपीआईपीएफटी) ने १८वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर और भाजपा के सांसद श्री भर्तृहरि महताब को अपना नया संयोजक और भाजपा के सांसद श्री तापिर गाओ को सह-संयोजक नियुक्त किया। ०७ अगस्त, २०२४ को हुए इस चुनाव के साथ ही फोरम का पुनर्गठन सफलतापूर्वक हो गया।

निर्वासित तिब्बती संसद और भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) द्वारा आयोजित रात्रिभोज के दौरान यह घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेन्पो सोनम तेनफेल, सांसद गेशे ल्हारम्पा अटुक शेतन, लोपोन थुप्टेन ग्यालत्सेन, शानेत्सांग धोंडुप ताशी, गेशे न्गाबा गंगरी, गेशे अतोंग रिनचेन ग्यालत्सेन और शेरिंग यांगचेन शामिल हुए। तिब्बत ब्यूरो (नई दिल्ली) में परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि जिग्मे जुंगने, आईटीसीओ के कार्यवाहक समन्वयक ताशी डेकयी और अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे।

स्पीकर तेनफेल ने नवनियुक्त संयोजक श्री भर्तृहरि महताब और सह-संयोजक श्री तापिर गाओ का अभिनंदन किया। इसके साथ ही एपीआईपीएफटी के पूर्व संयोजक राज्यसभा सांसद श्री सुजीत कुमार को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आभार प्रकट करते हुए उन्हें औपचारिक स्कार्फ (खटक) ओढ़ाया गया और बुद्ध की एक प्रतिमा भेंट की गई।

रात्रिभोज में एपीआईपीएफटी के पूर्व संयोजक श्री सुजीत कुमार, लोकसभा सदस्य श्री तापिर गाओ, भाजपा के पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद श्री मनोज तिग्गा, भाजपा के असम से लोकसभा सदस्य श्री अमरसिंग टिस्सो, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के असम से लोकसभा सांसद श्री जोयंता बसुमतारी, भाजपा की नगालैंड से राज्यसभा सांसद श्रीमती एस. फांगनोन कोन्याक, असम गण परिषद के असम से राज्यसभा सांसद श्री बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, भाजपा के पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद श्री जगन्नाथ सरकार, कांग्रेस के मणिपुर से लोकसभा सांसद एसोसिएट प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लोकसभा सांसद श्री इंद्र हैंग सुब्बा, कांग्रेस के असम से लोकसभा सांसद श्री प्रद्युत बोरदोलोई, लोकसभा सांसद श्री फणि भूषण चौधरी, लद्दाख से निर्दलीय लोकसभा सांसद श्री मोहम्मद हनीफ, लोकसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मेनका गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन में वरिष्ठ फेलो (विधान सहायता समूह) और दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ. पंकज पुष्कर शामिल हुए।

निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेंपो सोनम तेनफेल की आधिकारिक घोषणा के बाद एपीआईपीएफटी के संयोजक और सह-संयोजक ने अपने संबोधन में भारत और भारत के लोगों को उनके अटूट समर्थन और उदार आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने एपीआईपीएफटी के गठन और अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिब्बती मुद्दे की स्थिति के बारे में बात की।

श्री सुजीत कुमार ने अपने संबोधन में पिछले तीन वर्षों से एपीआईपीएफटी के संयोजक के रूप में कार्य करने को लेकर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कैसे ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक ने राज्य में तिब्बती निर्वासितों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पटनायक के तिब्बती समुदाय के साथ विशेष संबंधों को रेखांकित किया गया। इसके अतिरिक्त श्री कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीस ने पाकिस्तान के बजाय चीन को प्राथमिक खतरा बताया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रश्नगत सीमा हमेशा भारत-तिब्बत सीमा रही है, न कि चीन-भारत सीमा।

ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंटरी फोरम फॉर तिब्बत (एपीआईपीएफटी) के सह-संयोजक श्री तापिर गाओ ने बताया कि तिब्बती मुद्दों पर मुखर रहने वाले संयोजक कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने आगे बताया कि कैसे भारतीय हिमालयी राज्य और तिब्बत ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र और भारत का पड़ोसी देश है, जो अब चीन के कब्जे में है।

उन्होंने आगे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार तिब्बतियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में बात की और सभी तिब्बती राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई का आह्वान करते हुए तिब्बती पठार के महत्व पर एक स्वतंत्र शोध की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग नीति के माध्यम से चीन और परम पावन दलाई लामा के दूतों के बीच बातचीत को फिर से शुरू करने की बात दोहराई। उन्होंने तिब्बत पर चीन के झूठे आख्यान का मुकाबला करने में सभी के सहयोग का अनुरोध किया।

- तिब्बती संसदीय सचिवालय द्वारा दायर रिपोर्ट

◆ ०६. तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं के फोरम में भाग लिया

२३ अगस्त, २०२४

शिकागो। तिब्बती सांसद कर्मा गेलेक, लोबसंग ग्यात्सो सिथर और तेनज़िन चोएज़िन ने १९ से २२ अगस्त तक अमेरिकी राज्य इलिनोइस के शिकागो शहर में नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय नेताओं के फोरम में भाग लिया। तिब्बती निर्वासित संसद के सदस्यों को दुनिया भर के नेताओं से जुड़ने के लिए इस फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

१९ अगस्त को सांसद चोएज़िन को संसद सदस्यों और कार्यकर्ताओं सहित दुनिया भर के कुछ अन्य युवा राजनीतिक नेताओं के साथ ओबामा फाउंडेशन की एक विशेष आधिकारिक साइट के दर्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

अगली शाम सांसदों ने शुरुआती रात्रि स्वागत समारोह और सम्मेलन वॉच पार्टी में भाग लिया जो सम्मेलन को देखने, सम्मेलन की कार्यवाही पर चर्चा करने और वैश्विक राजनीतिक नेताओं के साथ नेटवर्क बनाने का एक शानदार अवसर था।
फोरम के दौरान सांसदों ने तिब्बत के अंदर की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करके साथी प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और तिब्बत के मुद्दे को उठाते हुए प्रश्न पूछकर वक्ताओं के साथ बातचीत की। सांसदों ने साथ ही बताया कि कैसे तिब्बत को अमेरिकी कांग्रेस में द्विदलीय समर्थन प्राप्त था और अब भी है तथा वर्तमान चुनाव चक्र के दौरान विदेश नीति पर चर्चा कुछ ऐसी है जो न केवल तिब्बत के लिए बल्कि वैश्विक जिज्ञासुओं के लिए भी प्रासंगिक है।

◆ ०७. तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिनिधि सभा के डिप्टी स्पीकर और ऑस्ट्रेलियन ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के सदस्यों से मुलाकात की

२० अगस्त, २०२४

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों- खेन्पो जामफाल तेनजिन, शेरिंग डोल्मा, चोएडक ग्यात्सो और तेनजिन फुंटसोक डोरिंग से मिलकर गठित संसदीय प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया में अपनी एडवोकेसी के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।

१९ अगस्त २०२४ को प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत सूचना कार्यालय में ऑस्ट्रेलिया-तिब्बत परिषद के कार्यकारी अधिकारी डॉ. ज़ो बेडफोर्ड के साथ बैठक की, जहां डॉ. बेडफोर्ड ने सुबह ऑस्ट्रेलिया के लोकतांत्रिक कामकाज का परिचय दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बौद्धिक मामलों के संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉ. ब्रायस वेकफील्ड के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में तिब्बती प्रतिनिधियों ने तिब्बत की गंभीर स्थिति के बारे में उनके साथ संवाद किया।

इसके बाद, तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने ऑस्ट्रेलियन ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्हें १२-सूत्रीय अपील-पत्र सौंपा गया और तिब्बत की वर्तमान गंभीर स्थिति से अवगत कराया गया। बैठक बहुत रचनात्मक रही और ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने हमें आश्वासन दिया कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। बैठक में सीनेटर डेबोरा ओ'नील, सांसद सुसान टेम्पलमैन, सीनेटर डीन स्मिथ, पूर्व उप प्रधानमंत्री और सांसद माइकल फ्रांसिस मैककॉर्मैक और सदन के पूर्व अध्यक्ष और सांसद एंड्रयू ब्रूस वालेस की गरिमामय उपस्थिति थी। उन्होंने मैकेलर्स से संघीय सांसद डॉ. सोफी स्कैम्प्स से भी मुलाकात की।

दौरे पर आए तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में उक्त सांसदों ने न्यूकैसल के संघीय सांसद और प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष शेरोन क्लेटन और सीनेटर जॉर्डन अलेक्जेंडर स्टील-जॉन के साथ संसद में रात्रिभोज का आयोजन किया।

प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रतिनिधि कर्मा सिंगे, चीनी संपर्क अधिकारी दावा सांग्मो और तिब्बत सूचना कार्यालय के सचिव ल्हावांग ग्यालपो, ऑस्ट्रेलिया-तिब्बत परिषद के डॉ. ज़ो बेडफोर्ड और कैनबरा तिब्बती समुदाय के कार्यकारी सदस्य थुप्टेन भी थे।

◆ ०८. भारत-तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तिब्बत के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया तथा वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया गया

tibet.net, ०७ अगस्त, २०२४

सोनीपत, हरियाणा। भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) की राष्ट्रीय परिषद ने ०३ और ०४ अगस्त २०२४ को हरियाणा के सोनीपत के समालखा में सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में २४ राज्यों के २६७ सदस्य एकत्रित हुए तथा तिब्बत और भारत-चीन संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करते हुए पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार किया।

इस बैठक में कई विशिष्ट अतिथियों और अधिकारियों की उपस्थिति रही, जिनमें केंद्रीय तिब्बत प्रशासन (सीटीए) के सुरक्षा विभाग की कालोन (मंत्री) डोल्मा ग्यारी भी शामिल थीं। वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। अन्य उल्लेखनीय हस्तियों में डॉ. के.सी. अग्निहोत्री (बीटीएसएम के संरक्षक), श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल (बीटीएसएम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष), स्वामी दिव्यानंद महाराज (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), श्री पंकज गोयल (बीटीएसएम के राष्ट्रीय महासचिव), श्री आर.के. खिरमे (कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया या सीजीटीसी-आई के संयोजक) और श्री प्रताप चंद्र (आरएसएस हरियाणा प्रांत के कार्यवाह) शामिल थे। दोनों दिनों में संगठन के सम्मानित मार्गदर्शक और संघ के वरिष्ठ प्रचारक, भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) के संरक्षक श्री इंद्रेश कुमार जी का अमूल्य मार्गदर्शन रहा।

इन विशिष्ट अतिथियों के अलावा, भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) की कार्यवाहक समन्वयक ताशी देकि और उनकी टीम ने तिब्बत से संबंधित पुस्तकें और ब्रोशर वितरित करके और दो दिवसीय सत्रों को कवर करके बैठक में योगदान दिया।

श्री पंकज गोयल ने अपने मुख्य भाषण में दलाई लामा के करुणा के संदेश को विश्व स्तर पर फैलाने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद श्री इंद्रेश कुमार की जोरदार इच्छाशक्ति के बल पर बीटीएसएम ने परम पावन दलाई लामा के ९०वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में वर्ष २०२५ को करुणा वर्ष घोषित किया। शांति के प्रतीक के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले परम पावन दलाई लामा के मील के पत्थर जन्मदिन को शांति, अहिंसा, भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देने वाले साल भर के समारोहों के रूप में चिह्नित किया जाएगा। बीटीएसएम ने भारत और दुनिया भर के समुदायों को शामिल करते हुए इन समारोहों को आयोजित करने के लिए एक समिति बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया।

श्री इंद्रेश कुमार जी ने तिब्बत में चल रहे चीनीकरण के संबंध में कहा कि बीटीएसएम ने चीन की इन कार्रवाइयों की निंदा की है। तिब्बत में चल रहे चीनीकरण की नीतियों में हाल ही में गोलोग में त्याग राग्या गंगजोंग शेरिग नोरबुलिंग स्कूल को बंद करना बड़ी घटना है। इस कार्रवाई का उद्देश्य तिब्बती नस्ल को चीनीकरण के एक व्यवस्थित अभियान के माध्यम से खत्म करना है। बीटीएसएम का दृढ़ विश्वास है कि चीन तिब्बती संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश में लगा हुआ है। मुख्य अतिथि माननीय कालोन डोल्मा ग्यारी ने अपने मार्मिक और सशक्त संबोधन में चीन की आक्रामक नीतियों की निंदा की और उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्थिति की तात्कालिकता और

गंभीरता पर जोर देते हुए इन हानिकारक इरादों के खिलाफ वैश्विक मान्यता और सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया।

बीटीएसएम ने पारंपरिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया को खारिज करते हुए अगले दलाई लामा के चयन के लिए अपनी खुद की पद्धति लागू करने के चीन के प्रयासों की भी कड़ी निंदा की। बीटीएसएम ने भारत और दुनिया से मौजूदा दलाई लामा के चयन संबंधी बयान का सम्मान करने की अपील करते हुए तिब्बती परंपराओं की आध्यात्मिक अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री इंद्रेश कुमार जी और कालोन डोल्मा ग्यारी दोनों ने इस मुद्दे की गंभीर प्रकृति पर जोर दिया, पुनर्जन्म प्रक्रिया को नियंत्रित करने के चीन के प्रयासों की निंदा की और तिब्बती आध्यात्मिक प्रथाओं की पवित्रता को बनाए रखने में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का आग्रह किया।

'चीन की सीमा चीनी दीवार है, बाकी कब्जा है'- बीटीएसएम का एक मजबूत नारा है जो यह घोषणा करता है कि दुनिया के लिए चीनी उत्पादों को खारिज करने और निर्वासित तिब्बती सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से तिब्बत संघर्ष को हल करने की वकालत करने का समय आ गया है। बैठक में तिब्बत पर चीन के कब्जे को वैश्विक मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और इसके खिलाफ जनमत जुटाया गया। इस मामले पर सीटीए प्रतिनिधि और सुरक्षा विभाग की कैबिनेट मंत्री की अंतर्दृष्टि अमूल्य थी, क्योंकि उन्होंने चीनी शासन के तहत तिब्बतियों द्वारा सामना किए जा रहे ऐतिहासिक और चल रहे अन्याय का विस्तृत विवरण दिया और एक दृढ़ और एकजुट अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का आग्रह किया।

बीटीएसएम ने भारत और दुनिया भर में हाल ही में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों को भी श्रद्धांजलि दी। इन आपदाओं से विस्थापित और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और उनके शीघ्र राहत और स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए बीटीएसएम ने युद्ध, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे मानवीय संघर्षों के कारण होने वाली हिंसा की निंदा की, अपनी जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति और घायलों और विस्थापितों के स्वस्थ होने और पुनर्वास के लिए प्रार्थना की। बैठक में सामूहिक रूप से इन कारणों से पीड़ित परिवारों के लिए शक्ति, साहस और धैर्य की प्रार्थना की गई।

बीटीएसएम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि बीटीएसएम के २०२४ के राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने तिब्बत और चीन-भारत संबंधों से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सफलतापूर्वक संबोधित किया। महत्वपूर्ण और प्रभावी वक्तव्य दिए गए और महत्वपूर्ण संदेश दिए गए, जैसे कि 'हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, इन चीजों के बारे में बात करते रहना चाहिए, अन्य समूहों और नए समूहों के साथ कार्यक्रम बनाते रहना चाहिए। हमें आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि हमारा आंदोलन चीन से तिब्बतियों द्वारा सामना किए जा रहे अन्याय के लिए है। भारत की सुरक्षा के लिए, हमें इसे जारी रखना चाहिए।'

बैठक के दौरान अपनाए गए संकल्प तिब्बती स्वायत्तता का समर्थन करने, सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और शांति, अहिंसा और सांस्कृतिक अखंडता के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बीटीएसएम के इन उद्देश्यों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक समर्थन जुटाकर चीनी विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए बीटीएसएम की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। बैठक में तिब्बती अधिकारों की वकालत करने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया गया और मानव पहचान की रक्षा करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के अपने मिशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

- भारत तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) की रिपोर्ट

◆ ०९. कालोन डोल्मा ग्यारी ने धर्मशाला में तिब्बत के पुराने समर्थक श्री डॉ. इंद्रेश कुमार का स्वागत किया

tibet.net, ०९ अगस्त, २०२४

धर्मशाला। ०८ अगस्त २०२४ को सुरक्षा विभाग की कालोन (मंत्री) डोल्मा ग्यारी ने तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी कुंचोक मिग्मार और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ कांगड़ा एयरपोर्ट पर आरएसएस के वरिष्ठ नेता डॉ. इंद्रेश कुमार जी का स्वागत किया।

मुख्य अतिथि के रूप में श्री डॉ. इंद्रेश कुमार को दोपहर बाद एक समारोह में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ द्वारा 'ब्रह्मर्षि वशिष्ठ पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। कालोन डोल्मा ग्यारी भी विशेष अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुईं।

यह दौरा एयरपोर्ट पर विमानन सुरक्षा सांस्कृतिक सप्ताह २०२४ समारोह के साथ हुआ। मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री शनि अंचल और टर्मिनल प्रबंधक सुश्री प्रशाली चौधरी ने विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और कांगड़ा एयरपोर्ट पर इस अवसर पर सुविधा प्रदान की।

- सीटीए के सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट

◆ १०. चीन : तिब्बतियों के जबरन गायब करने को रोकें, जबरन गायब किए गए सभी लोगों के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के मानकों के अनुरूप पुष्टि करें

tibet.net ३० अगस्त, २०२४

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बत सरकार के केंद्रीय प्रशासन (सीटीए) का सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग तिब्बत में तिब्बतियों के जबरन गायब होने के लगातार बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है और हिरासत में लिए गए तिब्बतियों के साथ चीनी सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार और दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करता है। हर साल, चीनी अधिकारी मनमाने ढंग से कई तिब्बतियों को गिरफ्तार करते हैं और जबरन गायब कर देते हैं। इसका मुख्य कारण इनके द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय पहचान की अभिव्यक्ति और दमनकारी नीतियों का विरोध है। गायब होने वालों में धार्मिक और सामुदायिक नेता, लेखक और संगीतकार, मानवाधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल हैं। ज़्यादातर मामलों में उन्हें जबरन गायब कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें अक्सर झूठे आरोपों में जेल की सज़ा होती है, जबकि अनेक मामले अभी भी अज्ञात हैं।

किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, जबरन गायब करने की सुनियोजित प्रथा मानवता के खिलाफ़ अपराध है। व्यक्तियों को जबरन गायब किए जाने से बचाने के लिए जारी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) घोषणा-पत्र के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि जबरन गायब किए जाने का कोई भी कृत्य अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो अन्य बातों के साथ-साथ कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार और यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन न होने के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य चीन लगातार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के प्रति पूर्ण अनादर प्रदर्शित करता है, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, अपने उत्पीड़न के तहत तिब्बतियों और अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों के साथ व्यवहार में वैश्विक मानकों की व्यवस्थित रूप से अवहेलना करता है।

जबरन गायब किए जाने के मामलों में सबसे प्रमुख मामला तिब्बत के ११वें पंचेन लामा गेधुन चोएक्यी न्यिमा का अपहरण है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च नेताओं में से एक हैं। महज छह साल की उम्र में चीनी अधिकारियों ने ११वें पंचेन लामा को उनके परिवार और चाद्रेल रिनपोछे के साथ १९९५ में अगवा कर लिया था। बार-बार चिंता जताने और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा आज तक हस्तक्षेप करने के बावजूद चीन ने पिछले २९ वर्षों से उनके ठिकाने या उनकी कुशलता के बारे में विश्वसनीय जानकारी रोक रखी है, जिससे वह दुनिया में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले राजनीतिक कैदियों में से एक बन गए हैं।

सिर्फ इसी साल कई तिब्बती 'गायब' हो गए हैं, जब चीनी अधिकारियों ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने से लेकर किताबें प्रकाशित करने तक के विभिन्न कारणों से उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया। इन मामलों में फुंटसोक, पेमा, समतेन, जोमकी, तमदिन और लोबसांग थाब्खे का जबरन गायब किया जाना शामिल है। हाल के वर्षों में एक प्रमुख मामला २०२० में गेंडुन ल्हुंड्रुप की मनमानी गिरफ्तारी है। उनकी मनमानी गिरफ्तारी के तीन साल से अधिक समय बाद भी, उनका ठिकाना और उनकी कुशलता के बारे में उनके परिवार को कुछ पता नहीं है।

जबरन गायब कर दिए जाने का पीड़ित पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिवार के सदस्यों पर इसका पंगु कर देने वाला प्रभाव पड़ता है, जो लंबे समय तक अपने प्रियजनों के भाग्य से अनजान रह जाते हैं, जो भयानक है। हाल ही में, तिब्बत से समाचार में लेखक तेनज़िन खेनराब की ५३ वर्षीय तिब्बती मां फुडे की दुखद मौत की सूचना मिली। उनके २९ वर्षीय बेटे को २०२३ में अपने फोन पर कई ई-पुस्तकों के साथ परम पावन दलाई लामा की एक तस्वीर रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनके बार-बार प्रयासों के बावजूद, चीनी पुलिस ने उनके बेटे के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। एक साल से अधिक समय तक अपने बेटे की भलाई के बारे में चिंता करने के अवसाद से पीड़ित होने के बाद मां फुडे का इस साल की शुरुआत में १७ फरवरी को निधन हो गया।

जेल में दस साल की सजा पाए गो शेरब ग्यात्सो और रिनचेन सुल्ट्रिम (कथित तौर पर इस साल की शुरुआत में रिहा) के मामले चीनी अधिकारियों की तिब्बती व्यक्तियों की गिरफ्तारी, हिरासत और सजा के बारे में विवरण छिपाने और केवल महत्वपूर्ण होने पर ही ऐसी जानकारी जारी करने की आदतों को दर्शाते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय दबाव डाला गया तब एक साल से अधिक समय बाद चीनी अधिकारियों ने बिना अधिक विवरण दिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक पत्र के जवाब में जुलाई- २०२१ में केवल उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की।

आज जब हम जबरन गायब किए जाने के पीड़ितों का ४१वां अंतरराष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, तो हम चीनी सरकार से तिब्बतियों के जबरन गायब होने को रोकने और उन लोगों की विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने का आह्वान करते हैं, जिनके भाग्य और ठिकाने अज्ञात हैं। पीआरसी सरकार के 'निर्दिष्ट स्थान पर आवासीय निगरानी' कानून की निंदा करते हुए हम चीन से सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और इसकी पुष्टि करने का आह्वान करते हैं। यह कानून चीनी पुलिस को लोगों को बिना सूचित किए छह महीने तक हिरासत में रखने और यातना देने और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार देता है। हम चीन से मांग करते हैं कि वह सभी जबरन गायब किए गए लोगों की सुरक्षा की बाबत इंटरनेशनल कन्वेंशन द्वारा घोषित नियमों की

पुष्टि करे जो जबरन गायब किए जाने की समाप्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हम संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों, अधिकार कार्यकर्ताओं और दुनिया भर के समर्थकों सहित अंतरराष्ट्रीय सरकारों और संगठनों से भी आग्रह करते हैं कि वे ११वें पंचेन लामा के मामले सहित मनमाने ढंग से गिरफ्तार और गायब किए गए तिब्बतियों के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए चीन पर दबाव डालना जारी रखें। जबरन गायब होना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का गंभीर उल्लंघन है। और चीन यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि जबरन गायब होने की पूरी तरह से जांच की जाए और यह उन लोगों के लिए अभिन्न क्षतिपूर्ति प्रदान करे जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस अमानवीय और अवैध कृत्य के भुक्तभोगी हैं।

- डीआईआईआर के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क, तिब्बत वकालत अनुभाग की रिपोर्ट

◆ ११. तिब्बती मुद्दों की विशेष समन्वयक ने परम पावन के समक्ष अमेरिका द्वारा तिब्बती मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की

tibet.net, २२ अगस्त, २०२४

धर्मशाला। परम पावन के अमेरिका से प्रस्थान से कुछ दिन पहले अमेरिकी सरकार में तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक अवर सचिव उजरा जेया और राष्ट्रपति के विशेष सहायक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लोकतंत्र और मानवाधिकार के वरिष्ठ निदेशक केली रज्जौक ने २१ अगस्त २०२४ को परम पावन दलाई लामा के साथ एक विशेष बातचीत की।

अमेरिका की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्रालय में तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक ने राष्ट्रपति बिडेन की ओर से परम पावन को अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दीं और अमेरिकी समर्थन की पुष्टि की। विशेष समन्वयक नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए अवर सचिव के रूप में भी कार्य करती हैं। सभा के दौरान उन्होंने तिब्बतियों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और उनकी विशिष्ट ऐतिहासिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता भी जताई।

विदेश मंत्रालय के मीडिया नोट में आगे कहा गया है कि अवर सचिव जेया ने अहिंसा और करुणा को बढ़ावा देने के लिए परम पावन दलाई लामा के आजीवन समर्पण की प्रशंसा की और तिब्बती सांस्कृतिक संरक्षण, तिब्बत के अंदर मानवाधिकारों के हनन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के चल रहे प्रयासों के लिए समर्थन पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त पीआरसी और परम पावन और उनके प्रतिनिधियों के बीच बातचीत को फिर से शुरू करने के तरीके पर बातचीत की।

परम पावन २२ अगस्त को यूबीएस एरिना में एक दीर्घायु प्रार्थना समारोह में भाग लेंगे और फिर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां २५ अगस्त को एक और दीर्घायु प्रार्थना निर्धारित है।

◆ १२. तिब्बत नीति संस्थान ने पूर्व भारतीय राजदूत दिलीप सिन्हा के साथ उनके हालिया कार्य 'तिब्बत में इंपीरियल गेम्स' पर एक टॉक सत्र आयोजित किया।

१४ अगस्त २०२४

धर्मशाला। तिब्बत नीति संस्थान ने ग्रीस में पूर्व भारतीय राजदूत श्री दिलीप सिन्हा से उनके विचार सुनने के लिए आज १४ अगस्त को अपने सम्मेलन कक्ष में एक सेमिनार आयोजित किया। श्री सिन्हा ने हाल ही में अपनी पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें चर्चा की गई है कि तिब्बत अपने पड़ोसी साम्राज्यों की भू-राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए एक खेल के मैदान के रूप में कैसे उभरा।.

वार्ता सत्र में तिब्बती सांसद दोरजी शेटेन और तेनज़िन चोएज़िन, वित्त विभाग के सचिव त्सेरिंग धोंडुप, सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव कर्मा चोयिंग, परम पावन दलाई लामा के कार्यालय के सचिव, छिमे रिगज़िन छोक्यापा और धर्मशाला में स्थित तिब्बती शोधकर्ता और मीडिया कर्मियों ने भाग लिया।

अतिथि वक्ता की प्रस्तुति से पहले तिब्बत नीति संस्थान के निदेशक सचिव दावा शेरिंग ने स्वागत भाषण दिया और पूर्व राजदूत के प्रकाशन 'इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत: द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सॉवरेंटी' पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की।

इसी तरह तिब्बत नीति संस्थान के उप निदेशक टेम्पा ग्यालत्सेन ज़मल्हा ने संक्षेप में तत्कालीन राजदूत का परिचय दिया, जिन्होंने सुरक्षा परिषद की सदस्यता के दौरान भारत के संयुक्त राष्ट्र मामलों के प्रमुख के रूप में भी काम किया है।

पूर्व भारतीय राजनयिक दिलीप सिन्हा ने अपनी दो घंटे की बातचीत में इस बात पर चर्चा की कि १९वीं शताब्दी में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच घनघोर प्रतिद्वंद्विता के दौरान तिब्बत कैसे एक केंद्र बिंदु बन गया और कैसे तिब्बत को एक बफर राज्य में बदल दिया गया। दो साम्राज्य जिन्होंने अंततः तिब्बत पर अपने झूठे दावे में चीन को लाभ पहुंचाया। वक्ता ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद तिब्बत के संबंध में भारत की विदेश नीति पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे तिब्बत की वर्तमान दुर्दशा गलत अनुमानों और दुर्भाग्य की शृंखला की परिणति है।

उनकी प्रस्तुति के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया और तिब्बत नीति संस्थान के प्रकाशनों को सराहना के प्रतीक के रूप में आगंतुक वक्ता को भेंट किया गया।

दोपहर बाद पूर्व राजदूत और उनकी पत्नी श्रीमी सिन्हा ने कशाग सचिवालय में सिक्योंग पेन्पा शेरिंग से मुलाकात की और बातचीत की।

◆ १३. चीन को तिब्बती मानवाधिकार कार्यकर्ता शेरिंग सो के उत्पीड़न को रोकना चाहिए

tchrd.org, ०५/०८/२०२४

'द तिब्बतन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी' तिब्बती मानवाधिकार कार्यकर्ता शेरिंग सो के निरंतर उत्पीड़न की कड़ी निंदा करता है। शेरिंग सो को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया था और युशू प्रान्त में स्थानीय पुलिस द्वारा १०-दिवसीय 'प्रशासनिक हिरासत' में लिया गया था।

पेशे से टूर गाइड का काम करनेवाली शेरिंग सो को चीनी अधिकारियों द्वारा पांच साल में चौथी बार हिरासत में लिया गया है। क्योंकि उन्होंने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) के नागचू (चीनी: नागु) प्रिफेक्चर के ड्रेचेन (चीनी : बाचेन) काउंटी में तीर्थयात्रा पर जा रहे दो तिब्बती भिक्षुओं के खिलाफ चीनी अधिकारियों द्वारा नस्लीय भेदभाव करने की गतिविधि को उजागर किया था। १० जून की शाम को स्थानीय समयानुसार लगभग शाम ०५ बजे ल्हासा और त्सारी की तीर्थयात्रा पर भिक्षुओं के एक समूह को ले जाते समय ड्रेचेन काउंटी के गोमरी टाउनशिप में स्थानीय पुलिस ने उनकी यात्रा में खलल डाल दिया। पुलिस ने कहा कि भिक्षुओं को अपनी यात्रा के लिए मठ प्रबंधन समिति और स्थानीय सरकार दोनों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बाद में उस रात स्थानीय पुलिस ने थुटोप नामग्याल और एक अन्य भिक्षु (सुरक्षा कारणों से नाम गुप्त रखा गया) सहित दो भिक्षुओं को हिरासत में ले लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की।

उनकी गिरफ़्तारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद शेरिंग सो ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि चीनी पर्यटकों को किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि तिब्बती भिक्षुओं को परमिट आवश्यकताओं के कारण प्रतिबंधों और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों से दोनों भिक्षुओं की तत्काल रिहाई की मांग की और कहा कि ड्रेचेन काउंटी पुलिस द्वारा उनकी हिरासत गैरकानूनी है और चीन के कानून और घरेलू नीतियों का उल्लंघन है। शुरुआत में ड्रेचेन काउंटी पुलिस ने भिक्षुओं को हिरासत में लेने की घटना से ही इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें 'पूछताछ' के लिए ले जाने की बात स्वीकार की। साथ ही यह भी कहा कि अगर वे भिक्षु

'सहयोग' करते हैं तो उनकी रिहाई में जल्द हो पाएगी।

स्थानीय पुलिस के साथ रिकॉर्ड की गई बातचीत में शेरिंग सो ने तिब्बती तीर्थयात्रियों को परेशान करने के लिए पुलिस द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की आलोचना की और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां नस्लीय एकता पर शी जिनपिंग की नीतियों का उल्लंघन हैं।

शेरिंग को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'तिब्बती लोग चीन के कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। इसलिए तिब्बतियों को हान चीनी के समान अधिकार होने चाहिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सरकार हमेशा नस्लीय एकता का दावा करते हैं, लेकिन मैं इस तरह की समस्याओं से क्यों जूझ रही हूं? अब मैं क्या कर सकती हूं? क्या आप (स्थानीय पुलिस) ड्रैचेन काउंटी के अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोक कर राष्ट्रपति शी की नीतियों को लागू नहीं करेंगे?' पुलिस ने जवाब देने में बहानेबाजी का सहारा लिया, जिसमें कहा गया कि विभिन्न विभागों के अलग-अलग नियम हैं। स्थानीय अधिकारियों से तीन घंटे तक गुहार लगाने के बाद भिक्षुओं को अंततः लगभग ०३ बजे रिहा कर दिया गया।

बाद में सो ने सोशल मीडिया पर घटना की पूरी रिकॉर्डिंग साझा की, जिसमें ड्रैचेन काउंटी पुलिस की भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों और दो भिक्षुओं की अवैध हिरासत को उजागर किया गया। इसके बाद, युशु तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर में अपने गृहनगर लौटने पर उन्हें २९ जून को 'सामाजिक स्थिरता को खतरे में डालने' के आरोप में हिरासत में लिया गया और बाद में दस दिनों की प्रशासनिक हिरासत के बाद ०८ जुलाई को रिहा कर दिया गया। यह चौथी बार है जब सो को चीनी सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना करने और तिब्बत के अंदर तिब्बतियों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करने के लिए हिरासत में लिया गया है।

पिछले साल दिसंबर में ड्रेचेन काउंटी की पुलिस ने शेरिंग सो को पंद्रह दिनों के लिए हिरासत में लिया था। उन पर यातायात जांच में सहयोग करने से इनकार करने और ऑनलाइन तरीके से गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया था।

अक्तूबर में शेरिंग सो ने वीचैट और डॉयिन सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर छोटे वीडियो पोस्ट किए, जिसमें तिब्बतियों के खिलाफ चीनी सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों को उजागर किया गया। उनके द्वारा जारी वीडियो ने बताया गया कि कैसे विभिन्न विभागों के अधिकारी तिब्बत में तिब्बती व्यवसायों को परेशान कर रहे हैं। व्यवसायियों को आज्ञापालक बनने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ते हैं। उन्हें अपना व्यवसाय बंद करने के लिए पूरा प्रयास करते रहे हैं।

परिणामस्वरूप, युशु पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें 'झगड़ा करने और परेशानियां भड़काने' के आरोप में १५ दिनों की प्रशासनिक हिरासत की सजा सुनाई। यह आरोप अक्सर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक समूहों, आलोचकों और असंतुष्टों के खिलाफ आधिकारिक कथन के अनुरूप होने और सरकारी नीतियों की आलोचना को रोकने के साथ ही सवाल और असहमति को दबाने के लिए लगाया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी नियंत्रित चीन की केंद्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक की सरकारें इन मनगढ़ंत आरोपों को परिभाषित करने और लागू करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करती हैं तथा आधिकारिक रुख में जरा भी हेरफेर होने पर उसे उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत करती हैं।

इसी तरह, १२ नवंबर २०२० की शाम को शेरिंग सो को दस अधिकारियों ने उनके शिनिंग स्थित घर से जबरन हिरासत में लिया और ल्हिका (ची: गाइड) काउंटी हिरासत केंद्र ले जाया गया। इसके बाद उन्हें १३ से २३ नवंबर तक १० दिनों की प्रशासनिक हिरासत में रखा गया और १००० युआन का जुर्माना लगाया गया। हिरासत के दौरान उन्हें केवल स्टीम्ड बन्स और गर्म पानी पर जीवित रखा गया। इसके अलावा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें धमकी भी दी गई। अधिकारियों ने उन्हें लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए उनकी मुखर वकालत को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए भी उन्हें अनेक प्रकार की धमकियां दीं।

२०१७ में युशु तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के स्थानीय तिब्बतियों के कानूनी अधिकार की वकालत करते समय शेरिंग सो को युशु प्रान्त के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो (पीएसबी) द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। युशु पीएसबी के आव्रजन प्रशासन प्रभाग के जामगा नामक एक अधिकारी ने उन पर बेरहमी से हमला किया और उनके सिर, चेहरे, छाती और पेट पर लात मारी। हालांकि प्रांतीय और प्रीफेक्चुरल पीएसबी के दोनों डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। उनके पति और दोस्तों की ओर से सो की गंभीर स्थिति के बारे में रिपोर्टों के बावजूद, अधिकारियों ने जिम्मेदारी से बचने के लिए एक नई कहानी गढ़ी। उन्होंने दावा किया कि शराब के नशे में आम नागरिकों द्वारा सो पर हमला किया गया था। इसीलिए उन्हें न्याय तक पहुंच से वंचित कर दिया गया।

शेरिंग सो सोल्हो (चीनी: हैनान) तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर में ल्हिका (चीनी: गाइड) काउंटी की मूल निवासी हैं। लेकिन युशु शहर में काम करती हैं और रहती हैं। वह तिब्बत वर्ल्ड टूर्स एंड ट्रैवल का संचालन करती हैं। सो को विशेष रूप से ल्हासा शहर, न्गारी और तिब्बत के अन्य भागों के साथ-साथ दुनिया भर में पर्यटन के आयोजन में विशेषज्ञता हासिल है।

शेरिंग सो ने लगातार तिब्बतियों के लिए समान अधिकारों की वकालत की है, जिसमें चीनी संविधान द्वारा गारंटी प्रदत्त आवागमन की स्वतंत्रता भी शामिल है। उनकी चिंताओं को दूर करने के बजाय चीनी सरकार ने उन्हें हिरासत में लेकर, डराकर और परेशान करके बार-बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है।

२०१८ में चीन की आवधिक समीक्षा के बाद अपने समापन अवलोकन भाषण में 'यूएस कमेटी ऑन रेसिकल डिसक्रिमिनेशन (नस्लीय भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र समिति)' ने चीनी सरकार से पासपोर्ट आवेदनों पर गैर-भेदभावपूर्ण निर्धारण और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और विदेश में यात्रा करने की इच्छा रखने वाले तिब्बतियों के लिए आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अपने नियमों और कार्रवाइयों को संशोधित करने का आह्वान किया था। चीनी संविधान में कथित रूप से किए गए वादों और वास्तविक कानूनी संशोधनों-कार्रवाइयों के बीच विरोधाभासी प्रक्रिया विशेष रूप से आपराधिक प्रक्रियाओं में विरोधाभासी प्रक्रिया एक कानूनी प्रणाली को जानबूझकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जांच को आमंत्रित करने और हेरफेर करने के लिए कूटरचित करता है। यह गंभीर मानवाधिकार हनन के लिए जवाबदेही से बचता है।

मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत कुछ ऐसे दबाव वाले मानवाधिकार मुद्दे हैं जो चीन में आपराधिक न्याय प्रणाली को कमजोर करते हैं। हज़ारों लोग औपचारिक आपराधिक प्रक्रिया के बाहर कानूनी अधिकारों को प्राप्त किए बगैर जेल में बंद हैं और पुलिस की मर्जी के अनुसार उन्हें १५ दिनों तक जेल में रहना पड़ रहा है। हम चीनी सरकार से अपील करते हैं कि वह अपने संविधान में निहित समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को बनाए रखे, भेदभावपूर्ण पासपोर्ट नियमों को तुरंत समाप्त करे और तिब्बतियों को तिब्बत में तीर्थ स्थलों पर आने-जाने का अधिकार दे।

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Acting Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि
कार्यवाहक समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः coordinator@indiatibet.net

August, 2024, Years: 45 Issue: 08 Regd No. : RNI 34636-79

न्यूयॉर्क में करीब १७,००० अनुयायियों ने परम पावन दलाई लामा के लिए दीर्घायु प्रार्थना की

भारत-तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तिब्बत के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया तथा वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया गया

निर्वासित तिब्बती संसद की ओर से दिल्ली में तिब्बत के पक्ष में अभियान